

MPSE-008 (PART-4)

STATE POLITICS IN INDIA

IMPORTANT QUESTIONS

ANSWERS IN BOTH HINDI AND ENGLISH

TOPIC 1

REGIONAL DISPARITIES IN HUMAN DEVELOPMENT IN INDIA.

Economic Disparities

India exhibits significant economic disparities across different regions. States like Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu have relatively high per capita income and industrial development, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh, and Odisha lag behind economically. This disparity affects overall human development, including education, healthcare, and living standards.

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताएँ देखी जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य आर्थिक रूप से पीछे हैं। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर सहित समग्र मानव विकास को प्रभावित करती है।

Educational Disparities

There are stark differences in educational attainment across states. Southern states like Kerala and Tamil Nadu have high literacy rates and better educational infrastructure, while northern and eastern

states such as Bihar and Jharkhand face challenges like high dropout rates, inadequate school facilities, and teacher shortages.

राज्यों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों में स्पष्ट अंतर हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में साक्षरता दर अधिक है और बेहतर शैक्षिक ढांचा है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे उत्तरी और पूर्वी राज्यों में उच्च ड्रॉपआउट दर, अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

Health Disparities

Healthcare facilities and health indicators vary widely across India. Kerala and Tamil Nadu have better healthcare infrastructure, higher life expectancy, and lower infant mortality rates. In contrast, states like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh struggle with poor healthcare services, high maternal and infant mortality rates, and malnutrition.

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य संकेतकों में व्यापक अंतर है। केरल और तमिलनाडु में बेहतर स्वास्थ्य सेवा ढांचा, उच्च जीवन प्रत्याशा और कम शिशु मृत्यु दर है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य खराब स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर और कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझते हैं।

Infrastructure Disparities

Infrastructure development, including roads, electricity, and sanitation, is uneven across the country. Urbanized and industrial states have better infrastructure, contributing to higher human development indices. Rural and less developed states often lack basic infrastructure, impeding their human development progress.

सड़कों, बिजली और स्वच्छता सहित बुनियादी ढांचे का विकास पूरे देश में असमान है। शहरी और औद्योगिक राज्यों में बेहतर बुनियादी ढांचा है, जिससे उच्च मानव विकास सूचकांक में योगदान मिलता है। ग्रामीण और कम विकसित राज्यों में अक्सर बुनियादी ढांचे की कमी होती है, जिससे उनके मानव विकास की प्रगति में बाधा आती है।

Government Policies and Interventions

Government policies and interventions play a crucial role in addressing regional disparities. Programs like the Backward Regions Grant Fund (BRGF), National Rural Health Mission (NRHM), and Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) aim to improve infrastructure, healthcare, and education in lagging regions. However, effective implementation and monitoring remain challenges.

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) जैसे कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार का लक्ष्य रखते हैं। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

TOPIC-2

DESCRIBE THE PATTERNS OF COMMUNAL POLITICS IN CONTEMPORARY INDIA.

Rise of Identity Politics

In contemporary India, identity politics based on religion has become more prominent. Political parties often appeal to religious identities to garner support, leading to the consolidation of votes along

communal lines. This trend has intensified in recent years, with parties using religious symbols, rhetoric, and leaders to mobilize voters.

वर्तमान भारत में धर्म आधारित पहचान की राजनीति अधिक प्रमुख हो गई है। राजनीतिक दल अक्सर समर्थन जुटाने के लिए धार्मिक पहचान का सहारा लेते हैं, जिससे सामुदायिक आधार पर वोटों का समेकन होता है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें दल धार्मिक प्रतीकों, भाषणों और नेताओं का उपयोग करके मतदाताओं को संगठित करते हैं।

Communal Polarization

Communal polarization refers to the division of society along religious lines, often exacerbated by political narratives. Incidents of communal violence, inflammatory speeches, and social media campaigns contribute to deepening this divide, creating an atmosphere of distrust and tension between different communities.

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अर्थ है धार्मिक आधार पर समाज का विभाजन, जिसे अक्सर राजनीतिक कथानकों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं, भड़काऊ भाषण और सोशल मीडिया अभियानों से यह विभाजन गहरा होता है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव का माहौल बनता है।

Electoral Strategies

Political parties sometimes use communal issues as a part of their electoral strategies. Campaigns may focus on religious sentiments, historical grievances, and promises to protect or promote the interests of specific religious groups. This can lead to the marginalization of minority communities and reinforce existing prejudices.

राजनीतिक दल कभी-कभी अपनी चुनावी रणनीतियों के हिस्से के रूप में सांप्रदायिक मुद्दों का उपयोग करते हैं। प्रचार अभियान धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक शिकायतों और विशिष्ट धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा या बढ़ावा देने के वादों पर केंद्रित हो सकते हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदायों का हाशियाकरण हो सकता है और मौजूदा पूर्वाग्रहों को बल मिल सकता है।

Impact of Social Media

Social media platforms have become a significant tool in the propagation of communal narratives. Misinformation, fake news, and provocative content can spread rapidly, often leading to communal tensions and conflicts. These platforms are used to mobilize support, organize protests, and amplify communal issues.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सांप्रदायिक कथानकों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। गलत सूचना, फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैल सकती हैं, जिससे अक्सर सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष होते हैं। इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग समर्थन जुटाने, विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने और सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

TOPIC-3

PATTERNS OF PROTEST MOVEMENTS IN INDIA

Historical Context and Evolution

Protest movements in India have a rich history, dating back to the colonial era. The freedom struggle against British rule, led by figures like Mahatma Gandhi, featured large-scale nonviolent protests. Post-independence, protest movements have evolved to address various social, economic, and political issues.

भारत में विरोध आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास है, जो औपनिवेशिक युग से शुरू होता है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद, विरोध आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकसित किया है।

Farmers' Protests

Agrarian distress has led to several large-scale farmers' protests in India. The recent protests against the farm laws in 2020-2021 highlighted issues related to minimum support prices, market deregulation, and farmers' livelihoods. These movements often involve mass mobilizations, sit-ins, and road blockades.

कृषि संकट ने भारत में कई बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध का नेतृत्व किया है। 2020-2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ हालिया विरोध ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार नियंत्रण हटाने और किसानों की आजीविका से संबंधित मुद्दों को उजागर किया। इन आंदोलनों में अक्सर जन जुटान, धरने और सड़क नाकेबंदी शामिल होते हैं।

Environmental Movements

Environmental concerns have sparked numerous protests across India. Movements like the Chipko Movement in the 1970s and the Narmada Bachao Andolan in the 1980s and 1990s focused on forest conservation, displacement due to dam projects, and sustainable development. These protests often involve grassroots activism and legal battles.

पर्यावरणीय चिंताओं ने पूरे भारत में कई विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन और 1980 और 1990 के दशकों में नर्मदा

बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन वन संरक्षण, बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापन और स्थायी विकास पर केंद्रित थे। इन विरोधों में अक्सर जमीनी स्तर पर सक्रियता और कानूनी लड़ाई शामिल होती है।

Social Justice Movements

Movements advocating for social justice, such as the Dalit movement, have played a significant role in India. These movements seek to address caste-based discrimination, untouchability, and social inequalities. Protests typically include rallies, awareness campaigns, and sometimes, confrontations with authorities.

सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन, जैसे दलित आंदोलन, भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ये आंदोलन जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। विरोधों में आमतौर पर रैलियां, जागरूकता अभियान और कभी-कभी, अधिकारियों के साथ टकराव शामिल होते हैं।

Student Movements

Student activism has been a vibrant part of India's protest landscape. Issues such as education policies, campus governance, and national politics have spurred student protests. Movements like the anti-Mandal Commission protests in the 1990s and recent protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) have seen significant student participation.

छात्र सक्रियता भारत के विरोध परिदृश्य का एक जीवंत हिस्सा रही है। शिक्षा नीतियों, कैंपस शासन और राष्ट्रीय राजनीति जैसे मुद्दों ने छात्र विरोधों को प्रेरित

किया है। 1990 के दशक में मंडल आयोग विरोध और हालिया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में महत्वपूर्ण छात्र भागीदारी देखी गई है।

Women's Movements

Women's rights movements have focused on issues such as gender equality, sexual violence, and reproductive rights. Movements like the anti-dowry protests, the Nirbhaya movement against sexual violence, and campaigns for women's reservation in politics have been pivotal in advancing women's rights in India.

महिला अधिकार आंदोलनों ने लैंगिक समानता, यौन हिंसा और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। महिला विरोध आंदोलन, यौन हिंसा के खिलाफ निर्भया आंदोलन और राजनीति में महिलाओं के आरक्षण के लिए अभियानों जैसे आंदोलन भारत में महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

Digital and Social Media Influence

In recent years, digital and social media have become powerful tools for organizing and amplifying protest movements. Platforms like Twitter, Facebook, and WhatsApp are used for mobilization, spreading awareness, and coordinating activities. This has increased the reach and impact of protests.

हाल के वर्षों में, डिजिटल और सोशल मीडिया विरोध आंदोलनों को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग जुटान, जागरूकता फैलाने और गतिविधियों का समन्वय करने के लिए किया जाता है। इससे विरोधों की पहुंच और प्रभाव बढ़ा है।

Scholarly Minds